

नेजाजी की जुबानी

“जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक के भविष्य का प्रश्न है, हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक आवश्यकता की उपज है तो वह नहीं मरेगा। यदि यह दार्शनिक आधार पर खड़ा है तो यह अवश्य ही आगे बढ़ेगा।”—नेताजी

जन गार्जन



वर्ष 39 अंक 6 हिन्दी मासिक नई दिल्ली जून-2024 विक्रमी संवत्-2078 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक - शुल्क: 100 रुपये

एक ऐसा चुनाव जिसमें एक तिहाई मतदाता अनुपस्थित

लोकतंत्र का उत्सव समाप्त हो गया। अप्रैल 19 से जून की पहली तारीख तक सात चरण में होने वाला चुनाव सम्पन्न हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 98.1 करोड़ मतदाताओं में से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने वर्ष 2024 के चुनाव में मतदान किया जो 65.79 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि 34 करोड़ लोगों ने मतदान किया ही नहीं जो प्रतिशत की दृष्टि से 35 प्रतिशत है। सीधा मतलब निकलता है कि 100 मतदाताओं में से 35 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अमेरिका दुनिया का तीसरा (आबादी की दृष्टि से) देश है जिसकी आबादी 34 करोड़ है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अमेरिका की आबादी के बराबर लोगों ने यहां मतदान ही नहीं किया है। वर्ष 2019 में कुल 91.19 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और 61.47 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। उस समय मतदान का प्रतिशत 67.4 प्रतिशत था। पिछले आम लोकसभा चुनाव से तुलना करने पर इस बार 2 प्रतिशत मतदान में गिरावट दर्ज हुई है।

चुनाव आयोग एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान में करोड़ों रुपए झोंके गए फिर भी एक तिहाई मतदाताओं ने इस चुनावी प्रक्रिया के प्रतिकूल क्यों रहे? राजनैतिक दल, चुनाव आयोग और आम समाज को किसी भी पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर इस तथ्य की जांच करनी चाहिए।

जी. देवराजन
महासचिव
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

हमारे देश की सरकार जेरेन्टोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है। जेनेन्टोक्रेसी एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें देश पर शासन वह करता है जो बहुसंख्यक आबादी को अभिव्यक्त नहीं करता है। भारत 'युवाओं के देश' के रूप में जाना जाता है जहां भारत की आबादी में 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों का भाग 50 प्रतिशत है।

देश में 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों का भाग कुल आबादी का 65 प्रतिशत है। जबकि संसद में 94.2 प्रतिशत संसद 35 वर्ष से आंक हैं।

निम्नलिखित तालिका देखें

उम्र	संसद में उपस्थिति
25-30	1.5 प्रतिशत
31-35	4.4 प्रतिशत
35-40	6.3 प्रतिशत
41-45	10.1 प्रतिशत
46-50	13.6 प्रतिशत
51-55	16.7 प्रतिशत
56-60	14.9 प्रतिशत
61-65	14.9 प्रतिशत
66-70	12.3 प्रतिशत

71-75 3.5 प्रतिशत

75 से ऊपर 1.8 प्रतिशत

(स्रोत: संसद रिकार्ड)

वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व में शहरों में उदासीनता तथा शिक्षित युवाओं द्वारा रूचि न लिए जाने की विवेचना होनी चाहिए। बंगलुरु भारत का आईटी (सूचना प्रौद्योगिक) क्षेत्र की राजधानी कहा जाता है और वहां विधानसभा चुनाव 2013 में मतदान प्रतिशत 63 प्रतिशत था जो वर्ष 2018 में घटकर 57 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2023 में 53 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 10 वर्षों में 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। दूसरे शहरों में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है। कोलकाता को छोड़कर देश के अन्य प्रमुख शहरों में यह गिरावट देखी जा सकती है। हैदराबाद 44.84 प्रतिशत, दक्षिण मुंबई 51 प्रतिशत, पुणे 49.89 प्रतिशत, नई दिल्ली 56.87 प्रतिशत, चेन्नई सेन्ट्रल 53.91 प्रतिशत रहा है। युवाओं का एक विशाल भाग मतदाता सूची में मतदान पत्र बनाकर, आधार नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के सहारे जुड़ गए थे।

बढ़ता भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है कि लोगों में राजनीति के प्रति अरूचि हो गई है। देश के मंत्रियों व सांसदों के यहां छापे पड़ने पर अकूत संपदा-नगदी का भंडार, गहने जेवरों जस्त हो रहे हैं तथा बेडरूम व शेष पेज 2 पर...

2024 के लोकसभा चुनावों में, लोगों ने भारत के संविधान और उसके गारंटीकृत लोकतांत्रिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सहकारी संघवाद जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए एक निर्णायक फैसला दिया। मोदी के इर्द-गिर्द बनी अजेयता की अभेद्य आभा अचानक बिखर गई है।

चुनाव एक अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में हुए, जिसमें असमानता, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का उच्च स्तर था।

चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने चुनाव का

संविधान की रक्षा का जनादेश

सामना करते हुए दावा किया था कि वे इस बार 400 (अब की बार 400 पार) से अधिक सीटें जीतेंगे। न केवल वे चार सौ सीटें पाने में बुरी तरह विफल रहे, बल्कि लोगों ने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को अकेले शासन करने के लिए बहुमत भी नहीं दिया। भाजपा की सीटें 2019 में 303 से घटकर 2024 में 240 हो गई हैं, जो 21% की कमी है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 292 सीटें मिलीं, जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिलीं। भाजपा को 36.

56% वोट मिले, जबकि उनके नेतृत्व वाले एनडीए को लगभग 42% वोट मिले। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक 36% से अधिक वोट पाने में सफल रहा। चुनाव के दौरान, आम लोगों को चिंता थी कि अगर भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करती है और एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें हासिल करता है, तो भारतीय संविधान को फिर से लिखे जाने और आरक्षण जैसे अधिकारों को समाप्त करने की संभावना हो सकती है। इस संदेह को इंडिया नाम बदलने और इसे भारत के रूप में पुनः ब्रांड करने

के आधिकारिक प्रयासों से बल मिला। पिछले दस वर्षों के भाजपा शासन के दौरान भारत ने अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का खतरनाक क्षरण देखा है। भारत की राजनीतिक प्रणाली, चुनावी लोकतंत्र की स्थिति को चुनावी निरंकुशता में बदल दिया गया है। साथ ही, राजनीतिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दशक में हम सबने असहाय होकर सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों और अन्य असंतुष्टों को जेल में जाते देखा है। नफरत फैलाने वाले

भाषणों, मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और सभी प्रकार के राजनीतिक विरोध के दमन के साथ-साथ भाजपा द्वारा संस्थागत कब्जे की प्रक्रिया भी चल रही है।

संसदीय प्रक्रियाओं का स्तर भी अभूतपूर्व रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया, जिसमें पूरा बजट बिना बहस के पारित हो गया और अधिकांश विधेयक बिना रिकॉर्ड किए मतदान के पारित हो गए। जांच एजेंसियों और अन्य संस्थानों का ज्यादातर (दुरुपयोग) विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और प्रतिद्वंद्वी दलों के टूटने को बढ़ावा देने के लिए किया गया। शेष पेज 6 पर...

हाल ही में सम्पन्न हुए आम लोकसभा के चुनावी नतीजों से परिलक्षित जनादेश भारत के संविधान की स्वीकृति, मोदी की गारंटी की अस्वीकृति और मोदी के निरंकुश अधिनायकवादी शासन पर अंकुश को स्पष्ट कर देता है। परन्तु श्री मोदी ने स्वयं को सर्वग्राही लोकतंत्र के मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया है। संविधान सदन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय पार्टी की बैठक हुई जहां श्री मोदी ने भारत के संविधान का सम्मान किया। संसद के केन्द्रीय हॉल में रखी हुई भारत के संविधान की एक प्रति को उठाकर माथे से लगाया। संविधान में वर्णित सिद्धांतों-जिससे करोड़ों-करोड़ देशवासियों में आशा, शक्ति एवं गरिमा का संचार होता रहा है के प्रति श्री मोदी ने अटूट समर्पण दर्शाया। उन्होंने आगे कहा: "डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त 'भारत का संविधान' और इसमें वर्णित उच्च मूल्यों के प्रति मेरे जीवन का एक-एक क्षण समर्पित है। इस संविधान के कारण ही मेरे जैसा व्यक्ति जो एक निर्धन और पिछड़ी जाति में पैदा हुआ-आज देश की सेवा का अवसर प्राप्त कर सका है।" यह एक भिन्न मोदी हैं क्योंकि हम सबने ऐसे मोदी को देखा है जो लगातार संविधान और उसके प्रारूपों और मानदण्डों की उपेक्षा व अवहेलना करते रहे हैं।

गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के उदय का स्मरण कीजिए। वे गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री बने अर्थात् गुजरात प्रान्त के हर नागरिक के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनते समय संविधान की शपथ भी लिया था, वहीं गुजरात दंगों के नाजुक क्षणों में उनकी निष्क्रियता अनैतिक तथा संविधान व लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध थी। उन्होंने अपने 'राजधर्म' का पालन नहीं किया था। तीव्रतम हिंदू-मुस्लिम विभाजन को हवा देकर इसे अपनी राजनीति का हथियार बनाया तथा कॉरपोरेट जगत की

संवैधानिक नैतिकता-प्रधानमंत्री से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न

अकूत धनसंपदा के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण किया। इस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को जात-धर्म ध्रुवीकरण की ओर मोड़ दिया। हमारे बहुदलीय संवदीय लोकतंत्र के लिए 'श्री मोदी' एक क्षण के लिए भी अनुकूल व्यक्ति नहीं है और हमारे समाज के सामाजिक व सांस्कृतिक ताने-बाने को गहरे आघात दिए हैं और विगत दस वर्षों के शासन में देश की अर्थव्यवस्था व गरिमा को रसातल में पहुंचा दिया है।

एक अनियमकवादी और संविधान विरोधी नेता के रूप में भयावह नोटबंदी का निर्णय स्वयं ही ले लिया। उन्होंने बार-बार संसदीय प्रणाली के प्रावधानों और मानदण्डों का खुला उल्लंघन

संपादकीय

किया है। बहुदलीय लोकतंत्र के प्रति मोदी प्रतिकूल रहे हैं और क्षेत्रीय दलों को लेकर असहज रहे हैं तथा उनको निगल जाने में तत्पर रहे हैं। कुछ माह पूर्व हम लोगों ने देखा था कि जब 151 सांसदों को निलंबित करने का असंवैधानिक कृत्य किया गया तथा इस आड़ में सीआरपीसी में संशोधन किए गए।

भाजपा-केन्द्रित से मोदी-केन्द्रित अलोकतांत्रिक राजनैतिक तर्ज पर चलकर इस बार भाजपा को अपने बल पर 240 सांसद प्राप्त हुए तो मोदी के बोलने के तौर-तरीके में बदलाव देखा गया तथा 'एनडीए की सरकार' शब्द क्रम का प्रयोग कर रहे हैं और क्षेत्रीय आकांक्षा व राष्ट्रीय हित में संतुलन साधने के सन्दर्भ में भाव व्यक्त किया है। हमारे संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है

और उसे संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार कार्य करना होता है। श्री मोदी का अलग रवैया है जो असंवैधानिक है जैसा कि अभी भी उन्हें संसद में बहुमत साबित करना है फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 17वीं किस्त जारी कर दिया है। प्रथम कैबिनेट की बैठक जब विभागों (मंत्रालयों) का वितरण भी नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण व शहरी आवास निर्माण हेतु तीन करोड़ अतिरिक्त घरों के लिए सहयोग राशि देने का निर्णय कर लिया। नए सरकार के वजूद में आने के बाद कैबिनेट कमेटी के पुनर्गठन के पूर्व ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा के कार्यकालों को विस्तार प्रदान कर दिया गया।

श्री मोदी के गत दो कार्यकालों में राष्ट्रपति और संसद के प्रति कैबिनेट प्रणाली की अवहेलना तथा संयुक्त जवाबदेही का लोप देखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के पास और अधिक शक्तियों का केन्द्रीकरण होता गया जिससे जवाबदेही की अवधारणा ही समाप्त हो गई। जलते हुए मणिपुर, कश्मीर और बेरोजगारी की समस्या में कोई रुचि नहीं दिखाई।

श्री मोदी ने अपने चुनावी यात्रा के वर्तमान दौर में खुलकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं और हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण का जोरदार प्रयत्न जारी रखा तथा मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच गए। संवैधानिक नैतिकता के प्रति निरादर का यह ताजा उदाहरण रहा है। पंथनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूलतत्व है तथा इसे अपनी वाक् क्षमता के बल पर कुचलने में सदैव से तत्पर रहे हैं।

हमें श्री मोदी पर ध्यान केन्द्रित रहना होगा। उन्हें संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों से बंधे रहना होगा। संविधान के प्रकाश में गठजोड़ सरकार चलाने हेतु आवश्यक संतुलन बनाए रखना अपरिहार्य होगा।

एक ऐसा चुनाव जिसमें एक तिहाई मतदाता ...

पेज 1 से जारी...

शौचालय में बरामदगी हो रही है। इस दृश्य से राजनीति के प्रति घृणा का माहौल फैल गया है। पढ़ लिखकर, परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी प्राप्ति हेतु घूस देना पड़े तो युवा के मन में राजनीति को लेकर घृणा का भाव क्यों न पसरे? जब परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाएं तथा परीक्षाफल धोखाधड़ी से तैयार हो तो इस तंत्र के विरुद्ध गुस्सा विकसित क्यों न हो? सार्वजनिक संपदा के निजीकरण में वृद्धि और आरक्षण लाभ का निरस्तीकरण दिखाई दे, सभी क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण तथा रोजगार की सुरक्षा समाप्त हो जाए तो युवाओं में विरोध तो व्याप्त होगा ही।

संसद व विधानसभाओं के सत्रों के दौरान होने वाली कुकृत्यों से बनने वाली छवि वर्तमान तंत्र के प्रति घृणा और उदासीनता

को पैदा करने वाली है।

संसद से एक तिहाई सांसदों को निलम्बित कर बिना विचार विनिमय के महत्वपूर्ण कानूनों को पारित किया जाए, लोकतंत्र की गरिमा गिराई जाए तो लोकतंत्र की प्राथमिक शिक्षा का लोप तो होगा ही। विपक्ष की आवाज को कुचलने पर ऐसा होगा ही। जब विधानसभाओं व संसद की कार्यवाहियों में नियमित बाधा डाली जाती हो, व्यक्तिगत अभियोग लगाकर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए और विधायिका द्वारा विचार विनिमय न हो तो ऐसा होगा ही तथा तंत्र घृणा का पात्र होगा ही।

इसके विपरीत इस बार तो चुनाव आयोग भी आलोचना का शिकार हुआ है। चुनाव आयोग ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया तथा शिकायतों पर उदासीन रहा तथा उसके लिए गए निर्णयों ने आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता को

गिरते देखा। चुनावी क्षेत्रों में पड़ने वाले मतदानों की संख्या का ब्योरा, आयोग ने नहीं दिया बल्कि इसे प्रतिशत में प्रस्तुत किया तथा ऐसा मतदान हो जाने के कई दिनों के बाद किया गया। इस सन्दर्भ में विपक्ष द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जवाब आयोग ने संतोषजनक नहीं दिया। वर्ष 2019 के चुनाव में हर चरण के चुनाव सम्पन्न होने पर प्रेसवार्ता के द्वारा चुनाव आयोग ने सीधे सामने आकर उत्तर दिया और जानकारी देने का कार्य किया था। यह सार्वजनिक कार्य इस बार नहीं हुआ। चुनाव आयोग मतदान के गिनती के पूर्व सामने आया और मीडिया से मिला। असहज प्रश्नों से चुनाव आयोग के बचने की चाल रही है जो उसने ऐसा किया। इवीएम पर उठने वाले प्रश्नों को संतोषप्रद तौर पर आयोग नहीं समझा पाया जिससे आम आदमी यह समझ पाए कि अम्पायर

पक्षपातविहीन है। जहां संदेह होना ही है, तो आम जनता वहां सहयोग नहीं देती है।

भारी मात्रा में प्रवासी मजदूर अपना मत देना चाहते हैं पर इस तंत्र में ऐसा नहीं कर सके। मतदाता सूची में उनका नाम होने पर भी वैसा वे नहीं कर पाए। लोकतंत्र के इस उत्सव में बदलते तौर-तरीके व आधुनिक तकनीक के बल पर उन्हें भी मतदान देने का अवसर मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए कि प्रवासी कामगार वर्ग जिस देश में हो वह मतदान दे सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 77 वर्ष बाद भी अनेक मूलभूत विषय हल नहीं हुए। गरीबी, बेरोजगारी, बिना छत (घर) और मेडिकल सुविधा न होना आज भी चुनावी वायदों को आकर्षक बनाने का कार्य

करते हैं। जिन सरकारों ने देश पर शासन किया अभी तक हर व्यक्ति को पेयजल भी नहीं प्रदान कर सके। जहां देश की सार्वजनिक सम्पदा कुछ शक्तिशाली लोगों की मुट्ठी में आ चुकी है शेष विशाल आबादी दो जून की रोटी जुटाने में असमर्थ हो रही है। चुनावी घोषणा पत्र बनाने वाले लोग यदि इसे छलावा या जुमला बोलें तो लोग राजनीति में कैसे विश्वास करें?

लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए मतदान आवश्यक है। परन्तु सामान्य तौर पर ऐसा निराशापूर्ण वातावरण तैयार हो जाता है जब आप किसी को भी मत दें और समाज का अराजनैतिकरण हो चुका हो। एक अराजनैतिक समाज तीव्रता से सर्वसत्तावाद (अधिनायकवाद) को रास्ता दे देता है। ऐसे में लोकतंत्र के अवसान की बेला जा जाती है।

2024 के चुनावों में भारतीय मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व

भारत में 2024 के आम चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आम मतदाता ही अंतिम किंगमेकर है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है और सिस्टम (षड्यंत्र तंत्र) से आसानी से धोखा नहीं खाता। इसके अलावा 67% भारतीय मतदाता अभी भी धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हिंदुत्व ताकतों द्वारा उन्हें चुप कराने और डराने के लिए किए गए जोरदार अभियानों के कारण उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने 2024 में चुनावी मैदान में कदम रखा, उसने आखिरकार उसकी उम्मीदों को झुठला दिया और कई लोगों का कहना है कि इसने देश को असहिष्णुता और बहुसंख्यकवाद के रसातल में गिरने से बचा लिया। पूरे चुनाव अभियान के दौरान सत्ताधारी पार्टी का मुखपत्र बने रहने वाले और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मोदी के नारे 'अब की बार 400 पार' के अनुसार भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिलने की भविष्यवाणी करने वाले चापलूस मीडिया को वास्तविक चुनाव परिणाम आने पर मुंह की खानी पड़ी। यह कहना भी गलत होगा कि भाजपा को आने वाले हथकड़ी का अंदाजा नहीं था। यह इस बात से स्पष्ट है कि चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रास्ता बदल लिया और अपने भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिकता के बीज बोने के अपने पुराने तरीके पर लौट आए, अपने भाषणों में मुसलमानों को निशाना बनाया, रोए और यहां तक कि खुद को भगवान बताने लगे। हालांकि, चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी सारी शरारतें धरी की धरी रह गईं। इसके अलावा, यहां जो अधिक दिलचस्प होगा वह उन कारकों का विश्लेषण करना होगा, जो भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार थे और जो वास्तव में 2024 के चुनावों में मुसलमानों द्वारा निर्भाई गई भूमिका को भी साबित करेंगे। 2024 में, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में 78 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे, उनमें से 24 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते या संसद में 4.42% की हिस्सेदारी हासिल की।

2019 के चुनावों में, 115 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और जिसमें 26 जीते थे। इसका मतलब है कि मौजूदा लोकसभा में दो मुस्लिम सांसद कम होंगे। एक बार जब संसद में मुस्लिम सांसदों का प्रतिशत दो अंकों के करीब था, ऐसा 1980 के चुनावों में हुआ था, जिसमें 49 मुस्लिम सांसदों ने संसद में सांसदों के प्रतिनिधित्व का 9.04% हासिल किया था। केवल 15 मुस्लिम बहुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और 8 अन्य में मुसलमान प्रमुख स्थिति में हैं, जिससे मुस्लिम-प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या केवल 23 हो जाती है। इन 15 निर्वाचन क्षेत्रों में, भाजपा ने छह (2014 से दो अधिक) और कांग्रेस ने नौ (2014 से तीन अधिक) में मुस्लिम उम्मीदवारों को नामित किया था। इस वर्ष, बसपा ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जो सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है। कांग्रेस 19 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ दूसरे स्थान पर थी, जबकि टीएमसी के पास इस बार तीसरे सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी (सपा) ने सिर्फ चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से तीन यूपी से लड़े, जबकि चौथा आंध्र प्रदेश से मैदान में था। सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों ने यूपी (22) चुनाव लड़ा, उसके बाद पश्चिम बंगाल (17), बिहार (सात), केरल (छह) और मध्य प्रदेश (चार) का स्थान रहा। 2024 में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या का एक कारण इंडिया ब्लॉक था। पिछले चुनावों में, मुसलमानों ने आम तौर पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट दिया था। इसलिए, 2019 के लोकसभा में, मुस्लिम वोट कांग्रेस और सपा के बीच विभाजित हो गए, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट एकजुट रहे। मुस्लिम विधायकों की घटती संख्या को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि अधिकांश विपक्षी दल भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ध्रुवीकरण की आशंका के चलते मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतराते हैं। यह लोकसभा की ताकत

का 5% से भी कम है, जो भारत में मुसलमानों की कुल आबादी से बहुत कम है, जो 2011 की जनगणना में 14% थी।

2024 में मुस्लिम विरोधी एकजुटता के कारणों को राम मंदिर के अभिषेक और सभी क्षेत्रों में पुराणों की कथा के प्रभुत्व में देखा जा सकता है। नीतिगत स्तर पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर मोदी सरकार के कदमों को लेकर आशंकाएँ थीं: कई लोगों ने इन्हें समुदाय को अलग-थलग करने के लिए सरकारी उपकरण के रूप में देखा। इसके अतिरिक्त, दंड के बिना लिंगिंग की बढ़ती घटनाओं के साथ अंतर-समुदाय संबंध और भी खराब हो गए।

हालांकि, भले ही कोई इस बात से खुश हो कि इतने सारे मुस्लिम उम्मीदवार जीते, लेकिन यह क्षण तथाकथित मुस्लिम धार्मिक,

राजनीतिक और सामाजिक नेताओं और यहाँ तक कि आम मुसलमानों को भी रुकने और सोचने का अवसर देता है कि क्या भाजपा की हार उनकी जीत है या नहीं। पार्टी के उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों के रूप में मुसलमानों के प्रति भाजपा की घृणा के स्पष्ट हो जाने के अलावा, परिणामों के कारण हमें यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि स्वतंत्रता के 77 साल बाद भारतीय मुसलमान कहाँ खड़े हैं। क्या वे राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक या सामाजिक रूप से सफल रहे हैं या वे लगातार सरकारों से सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद करते हुए नीचे चले गए हैं, लेकिन एक समुदाय के रूप में, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दम पर पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं।

हालांकि, 1947 से भारतीय मुसलमानों ने धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है,

फिर भी वे अखिल भारतीय उपस्थिति और स्वीकार्यता के साथ अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने में सक्षम नहीं हैं। इस उदासीन दृष्टिकोण के पीछे क्या कारण माना जाना चाहिए? उनकी ओर से इच्छा की कमी या अक्षमता?

हाल ही में एक्स पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें मुस्लिम उलेमा के एक नेता ने कहा कि वह भारतीय मुसलमानों की मुस्लिम राजनेता का समर्थन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वास्तव में यह उनके जैसे धार्मिक नेता हैं जिन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय को धोखा दिया है और हमेशा भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक रूप से उभरने की किसी भी योजना को विफल किया है और इसका परिणाम संसद में मुसलमानों का खराब प्रतिनिधित्व है।

(असद मिर्जा, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणीकार। सौजन्य: नागालैंड टाइम्स)

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा को पुनः हमेशा के लिए आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से बाहर करना होगा

(क्यूबा गणराज्य के विदेश मंत्रालय का बयान)

अमेरिकी आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 15 मई 2024 को, देश के विदेश मंत्री ने कांग्रेस को एक और मनमाना रिपोर्ट सौंपा, जो आम तौर पर बिना किसी अंतरराष्ट्रीय जनादेश या मान्यता वाले देशों का वर्णन करती है। इस बार, उन्होंने चार देशों को सूचीबद्ध किया जो कथित तौर पर '2023 कैलेंडर वर्ष के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के आतंकवाद विरोधी प्रयासों के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं करते हैं।' हाल के वर्षों में जो हुआ है, उसके विपरीत, सूची में क्यूबा को ऐसे देशों में बदनाम करने के लिए शामिल नहीं किया गया है।

फिर भी, विदेश विभाग ने क्यूबा को उन देशों में से एक के रूप में रखा है जो कथित तौर पर आतंकवाद को 'प्रायोजित' करते हैं। यह पूरी तरह से एकतरफा और निराधार सूची के

अलावा कुछ नहीं है, जिसका एकमात्र उद्देश्य संप्रभु राज्यों को बदनाम करना और उन पर जबरदस्ती आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बहाने के रूप में काम करना है, जैसा कि क्यूबा पर बेरहमी से लगाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार से इस तरह के अन्याय को संशोधित करने की मांग न केवल क्यूबा के लोगों और कई सरकारों द्वारा (विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में) बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों और कई अमेरिकी राजनेताओं द्वारा भी दृढ़ता से और बार-बार ऐसी मांग की जाती रही है।

स्पष्ट और पूर्ण सत्य यह है कि क्यूबा आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करता है, बल्कि वह इसके बजाय इसका शिकार रहा है, जिसमें राज्य आतंकवाद भी शामिल है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी पुष्टि इस विषय में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और यह

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, उसके विदेश विभाग और उसकी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। वे इस बात से भी पूरी तरह अवगत हैं कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबंध, कार्रवाई और डराने वाला प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है, जो किसी भी राज्य पर स्वतः ही पड़ता है, चाहे सच्चाई कुछ भी हो।

यह स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है कि क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पूर्ण सहयोग करता है। क्यूबा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी ऐसा करता है। यह एक व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य है और इसके बारे में जनता की राय को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ईमानदारी से कार्य करने और सही काम करने के सभी विशेषाधिकार हैं।

हवाना, 15 मई 2024. (क्यूबामिनरेक्स)

दुनिया का पहला 'एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट घोटाला'

31 मई को भारत के शेयर बाजारों में अचानक से हलचल बढ़ गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर खरीदे और बेचे गए शेयरों का मूल्य पिछले दिन से दोगुना हो गया। एक दिन में शेयरों के कारोबार में इतनी बड़ी उछाल बहुत कम देखने को मिलती है, भले ही कोई बड़ी चौकाने वाली खबर हो। उदाहरण के लिए 12 मार्च 2020 को जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया, तो शेयर बाजार की गतिविधियां पिछले दिन से 22% बढ़ गई थी, लेकिन तब भी यह दोगुना नहीं हुई थी। शेयर बाजार की ट्रेडिंग गतिविधि पिछली बार 16 मई, 2014 को दोगुनी हुई थी, जब चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे और नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, जो तीन दशकों में पहली बार हुआ था, जो तब बहुत बड़ा आश्चर्य था। जिज्ञासु प्रश्न यह है कि-31 मई, 2024 को शेयर बाजार की गतिविधि के दोगुना होने के लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक खबर या परिवर्तन विशेष क्या था? कुछ भी नहीं। केवल इतना ही कि यह मतदान के अंतिम चरण से एक दिन पहले था, एक ऐसा विवरण जो पहले से ही ज्ञात था। 31 मई को शेयर बाजार में भारी वृद्धि को समझाने के लिए कोई बड़ी खबर नहीं थी। फिर, बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी तीव्र ट्रेडिंग में कौन लोग शामिल थे? जबकि विशिष्ट निवेशक विवरण निजी जानकारी है और उपलब्ध नहीं है, एनएसई निवेशक श्रेणी के अनुसार शेयर बाजार की गतिविधि प्रकाशित करता है-खुदरा निवेशक (आम लोग), भारतीय म्यूचुअल फंड जैसे घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी निवेशक। पता चला कि उस दिन शेयरों की कुल खरीद में 58% हिस्सा विदेशी निवेशकों का था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि पिछले सप्ताह के हर दिन, विदेशी निवेशक इतने बड़े अनुपात में खरीद नहीं कर रहे थे और शुद्ध विक्रेता थे। फिर यह दिलचस्प है कि 31 मई को, जब कोई बड़ी खबर नहीं थी, विदेशी निवेशकों का एक समूह अचानक भारत में तेजी से आगे बढ़ गया और शेयरों की भारी खरीद में शामिल होने का फैसला किया। विदेशी निवेशकों के एक समूह द्वारा

इस रहस्यमय शेयर-खरीद गतिविधि को केवल अगले दिन क्या हुआ, उससे ही समझाया जा सकता है।

अगले दिन एग्जिट पोल जारी किए गए और जादुई रूप से, हर एक एग्जिट पोल ने भाजपा गठबंधन के लिए भारी जीत की भविष्यवाणी की, कुछ ने तो 400 सीटें भी जीता दीं, जो चार दशकों में पहली बार हुआ। लेकिन फिर, एग्जिट पोल जारी होने से एक दिन पहले शेयर बाजार की गतिविधि दोगुनी कैसे हो गई, जबकि संभवतः केवल पोलस्टर्स और उनके मीडिया संगठनों को ही भविष्यवाणियों के बारे में पता था और उन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था? निश्चित रूप से, यह महज संयोग नहीं हो सकता है कि शेयर बाजार में कारोबार के दोगुना होने जैसी अत्यंत दुर्लभ घटना ठीक एक दिन पहले हुई, जब कई एग्जिट पोल ने सर्वसम्मति से मोदी की भारी जीत का अनुमान लगाया था! जब सप्ताहांत के बाद 3 जून को शेयर बाजार फिर से खुला, तो यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कि एग्जिट पोल द्वारा मोदी के तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी के कारण था। जाहिर है, विदेशी निवेशकों के जिस समूह ने 31 मई को अचानक बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे, उनके मूल्य में भारी वृद्धि देखी गई। 4 जून को, जब वास्तविक परिणाम घोषित किए जा रहे थे, तो यह स्पष्ट हो गया कि हर एक एग्जिट पोल गलत था, और मोदी को साधारण बहुमत पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। शेयर बाजार में भगदड़ मच गई और बाजार धराशायी हो गया। मतगणना के दिन ही इसके मूल्य में 30 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। तब तक विदेशी निवेशकों ने अपने शेयर बेच दिए थे और भारी मुनाफा कमाया था। खुदरा निवेशकों (आम लोगों) के विशाल बहुमत ने अपने शेयर मूल्य में गिरावट देखी और भारी नुकसान उठाया। यह कहानी का सरल पक्ष है। इस गाथा का दूसरा, तकनीकी रूप से अधिक जटिल पक्ष यह है कि शेयर डेरिवेटिव्स का उपयोग करके शेयर बाजारों में सट्टेबाजी के माध्यम से भी भारी मुनाफाखोरी की गई थी,

जिसके माध्यम से निवेशक शेयर बाजारों में वृद्धि और गिरावट दोनों से लाभ कमा सकते हैं। ये डेरिवेटिव निवेशक तब सबसे अधिक लाभ कमा रहे हैं जब जबरदस्त अस्थिरता होती है, जो कि भारतीय शेयर बाजारों ने एग्जिट पोल और वास्तविक परिणामों के बीच अनुभव किया। डेटा दिखाता है कि 31 मई और 4 जून के बीच डेरिवेटिव्स में भी भारी कारोबार हुआ। अगर एग्जिट पोल ने भाजपा की भारी जीत की भविष्यवाणी नहीं की होती, तो शेयर बाजार 3 जून को इतना ऊपर नहीं उछलता और परिणामस्वरूप 4 जून को इतनी तेजी से नहीं गिरता। यह एग्जिट पोल ही थे जिन्होंने डेरिवेटिव निवेशकों के लिए इस वांछित अस्थिरता को प्रेरित किया। यह जानबूझकर किया गया या अनजाने में, यह 30 लाख करोड़ रुपये का सवाल है। संक्षेप में, यह डेटा के माध्यम से स्पष्ट है कि एग्जिट पोल और चुनाव परिणामों के आसपास शेयर बाजार में संदिग्ध और रहस्यमय गतिविधि थी, जिससे

विदेशी निवेशकों के एक समूह को फायदा हुआ, और लाखों भारतीय छोटे निवेशकों को धन की हानि हुई।

शेयर बाजार की इन दिलचस्प गतिविधियों का एक अनुमान यह है कि निवेशकों के एक खास समूह के पास एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों तक उनकी सार्वजनिक होने से पहले ही पहुंच थी और उन्होंने इस 'अंदरूनी (गलत) सूचना' से लाभ कमाया। प्रतिभूति कानूनों के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और अधिकांश देशों में इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। कुछ स्पष्ट प्रश्न जो मन में आते हैं, वे हैं:

1. ये विदेशी निवेशक कौन हैं जिन्होंने 31 मई को भारत के शेयर बाजारों में भारी मात्रा में पैसा लगाया?
2. क्या उन्होंने एग्जिट पोल से लाभ कमाने के लिए उनकी भौतिक, गैर-सार्वजनिक, अंदरूनी जानकारी पर काम किया?
3. एग्जिट पोल करने वालों या इसमें शामिल मीडिया संगठनों से उनका क्या संबंध है?
4. ये निवेशक किसके पैसे या

किसकी ओर से निवेश कर रहे थे? 5. इन निवेशकों को कारोबार के इन दो दिनों में कितना लाभ हुआ?

9 अक्टूबर, 2021 को ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर को एक अनोखे घोटाले में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने पक्ष में जनमत सर्वेक्षणों में हेराफेरी की, मीडिया को इन सर्वेक्षणों को दिखाने के लिए मजबूर किया और अपना चुनाव जीत लिया। भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं ने शायद इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया हो। घटनाओं के कालक्रम और शेयर बाजार के आंकड़ों से, कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि न केवल चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए बल्कि शेयर बाजारों का उपयोग करके लाभ कमाने के लिए भी एग्जिट पोल का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने शायद दुनिया का पहला 'एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट घोटाला' देखा हो!

(प्रवीण चक्रवर्ती द्वारा - सौजन्य डेकन हेराल्ड)

ओडिशा विधानसभा चुनाव में एआईएफबी उम्मीदवारों को प्राप्त मत

नं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	उम्मीदवार का नाम	वोट सुरक्षित
1	चिकित्ति	कॉम. बिभुषेन्द्र पाधी	371
2	बेरहामपुर	कॉम. शमीम बेगम	120
3	गोपालपुर	कॉम. कुमारी ममता	265
4	दियापहांडी	कॉम. पिटू प्रधान	549
5	परताखेमंडी	कॉमरेड पी. गुरुतीकृष्ण	429
6	जयपुर	कॉम. बी. हरि राव	516
7	धर्मगढ़	कॉम. टंकाधा सबर	1477
8	लांजीगढ़	कॉम. उधवा नायक	1629
9	नरला	कॉम. (डॉ.) सिवाराम नायक	521
10	कोयपुट	कॉम. धनुर्जय हंतल	504
11	भंजनगर	कॉम. राजू नायक	659
12	भुवनेश्वर सेंट्रल	कॉम. लक्ष्मी डोर	91
13	एकाम्र भुवनेश्वर	कॉमरेड संतोष कुमार जति	102
14	कांटाबांजी	कॉम. अभिराम धरुआ	1217
15	पटनागढ़	कॉमरेड चैतन्य बैंग	1169
16	तालचेर	कॉमरेड मनोज कुमार जेना	162
17	नीमापारा	कॉम. जितेन्द्रिय बेहरा	158
18	काकटपुर	कॉमरेड रवीन्द्र नाथ कंडी	129

मेक्सिको के लोगों ने भारी बहुमत से मजदूर समर्थक प्रगतिशील शीनबाम को राष्ट्रपति चुना

एक ऐतिहासिक चुनाव में, मेक्सिको के मतदाताओं ने मजदूर समर्थक, प्रगतिशील उम्मीदवार क्लाउडिया शीनबाम को छह साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना, जो पहली महिला और पहली यहूदी व्यक्ति हैं।

शीनबाम ने अपने विजय भाषण में घोषणा की, 'हम महिलाएँ राष्ट्रपति पद पर पहुँची हैं।' 'लेकिन हम सभी के लिए शासन करने जा रही हैं।'

'गणतंत्र के 200 वर्षों में पहली बार, मैं मेक्सिको की पहली

महिला राष्ट्रपति बनूँगी। और जैसा कि मैंने अन्य अवसरों पर कहा है, मैं अकेली नहीं आई हूँ। हम सभी आए हैं, अपनी नेत्रियों के साथ, अपने पूर्वजों, अपनी माताओं, अपनी बेटियों और अपनी पोतियों के साथ जिन्होंने हमें अपनी मातृभूमि दी।'

शीनबाम निवर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की सहयोगी हैं, जिन्हें एमएलओ कहा जाता है और जो उनकी मोरेना पार्टी की उम्मीदवार हैं। वे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति और पहली यहूदी

राष्ट्रपति होंगी, जो कि मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक राष्ट्र है। वह 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगी। मैक्सिकन राष्ट्रपति केवल एक कार्यकाल तक ही सेवा कर सकते हैं।

प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता

वह मेक्सिको की पहली नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति भी होंगी, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु पैनल में सहकर्मियों के साथ पुरस्कार साझा करेंगी, जिसने ग्लोबल वार्मिंग में तेजी की जांच की और उसे प्रचारित किया। शीनबाम ने मेक्सिको के प्रमुख

विश्वविद्यालय से ऊर्जा इंजीनियरिंग में पीएचडी की है।

जबकि शीनबाम का शीर्ष कार्य आपराधिक गिरोहों और बढ़ती आय असमानता से लड़ना होगा - जिसमें वहाँ एक बड़ा लिंग अंतर भी शामिल है, पूर्व मेक्सिको सिटी मेयर, जो एएमएलओ के कैबिनेट के सदस्य भी थे, को एक और समस्या का समाधान करना पड़ सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में क्या करना है।

रिपब्लिकन पार्टी के संभावित अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रम्प न केवल मैक्सिकन विरोधी, अप्रवासी विरोधी और रंगभेद विरोधी हैं, बल्कि अब वे एक दोषी अपराधी भी हैं। और भले ही वे नवंबर में अमेरिका में प्रवेश करें, मैक्सिकन कानून अपराधियों को राष्ट्रपति पद की छूट के बिना प्रवेश करने से रोकता है, चाहे उनकी अपील अदालतों में कहीं भी क्यों न हो। अपराधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले अन्य देशों में कनाडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। मेक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनौपचारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दो महिला-दो पुरुष की दौड़ में शीनबाम अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, जोचिटल गैल्वेज से दो-से-एक अंतर से नहीं जीतीं, लेकिन मैक्सिकन प्रतिनिधि सभा में मोरेना बहुमत हासिल किया और सीनेट में बहुमत के करीब पहुँच गई। अपने विजय भाषण में शीनबाम ने एएमएलओ की प्रशंसा की और मेक्सिको की बढ़ती आय असमानता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी कई नीतियों को जारी रखने का वादा किया। मेक्सिको के कॉर्पोरेट वर्ग, जिनमें से कई कार्टेल के समर्थक थे, ने शेयर बाजार के औसत में मामूली गिरावट के साथ शीनबाम और मोरेना की भारी जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। शीनबाम ने कार्टेल अपराधियों के लिए 'कारणों को संबोधित करने और शून्य दंड की ओर बढ़ना जारी रखने की रणनीति बनाकर'

कार्टेल का मुकाबला करने का वादा किया। और मैक्सिकन आय असमानता इसके कार्यबल में लिंग और वर्ग असमानता को भी दर्शाती है। घरेलू कामगारों को काम पर कठोर परिस्थितियों और बढ़ती हिंसा का सामना करना पड़ता है। मैक्सिकन राज्यों में नारीवादी समूहों-जिन पर अभी भी पुरुष राजनेताओं का वर्चस्व है- को गर्भपात की पहुँच और यौन और प्रजनन अधिकारों के लिए लड़ते रहना चाहिए। और महिलाओं को निशाना बनाकर हत्या की दर बढ़ गई है। पदभार ग्रहण करने पर एएमएलओ की पहली कार्रवाइयों में से एक मेक्सिको के न्यूनतम वेतन को दोगुना करना था। अन्य में बेहतर वृद्धावस्था पेंशन की स्थापना और युवा लोगों को आपराधिक कार्टेल से दूर रखने के लिए कॉलेज छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल था। और उन्होंने कुख्यात भ्रष्ट राष्ट्रीय पुलिस को भंग कर दिया, कानून प्रवर्तन को सशस्त्र बलों को सौंप दिया। शीनबाम को अपनी सीमा पर प्रवासन में अमेरिकी कार्रवाई के प्रभाव और उसके बाद के प्रभावों से भी निपटना होगा। बिडेन पहले से ही ट्रम्प द्वारा राष्ट्रपति रहते समय लागू किए गए कई अप्रवासी विरोधी पुलिस को लागू कर रहे हैं। बिडेन ने 4 जून को एक नई सीमा सुरक्षा योजना बनाई। इसमें सभी शरणार्थियों को लगभग स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और अन्य प्रवासियों को उत्तरी मैक्सिको में सीमा के दक्षिण में शिविरों में रहने के लिए मजबूर किया गया है। ट्रम्प का कहना है कि वह अमेरिका में सभी 10 से 11 मिलियन अनिर्दिष्ट लोगों को निर्वासित करेंगे, पहले उन्हें इकट्ठा करके जेल शिविरों में डाल देंगे। वह विदेशी प्रवासियों को अपराधी और बलात्कारी कहते हैं, और सीमा को बंद करने और मुसलमानों और उन लोगों को प्रतिबंधित करने का वादा करते हैं जिन्हें वह 'शिटहोल देश' कहते हैं। ट्रम्प जिन देशों की आलोचना करते हैं, उनमें मैक्सिकन भी शामिल हैं, वहाँ से आने वाले प्रवासी अक्सर अस्वेत रंग के लोग होते हैं। (सौजन्य: पीपुल्स वर्ल्ड)

आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएफबी उम्मीदवारों को प्राप्त मत

नं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	उम्मीदवार का नाम	वोट सुरक्षित
1	कैकालुरु	कॉमरेड एल. वीरा शिवाजी	213
2	राजमपेट	कॉमरेड के. सुब्बम्मा	695
3	भीमावरम	कॉम. श्रीनिवास राजू	221
4	पुलिवेदुला विधानसभा सीट पर	कॉमरेड कर्ण रमेश कुमार रेड्डी	146
5	बडवेल	कॉमरेड सिंगमाला वैकटेश्वरु	64
6	गोपालपुरम	कॉम. बथुला वेणु	206
7	Gannavaram	कॉम. डोंडापति आनंद प्रसाद	256
8	उत्पाद	कॉमरेड पी. बंगारुमुनि रेड्डी	43
9	मैदुकूरु	कॉम. अवुतला राजेश्वर रेड्डी	53
10	अनंतपुर	कॉमरेड के.सूर्या श्रेष्ठर रेड्डी	116
11	पन्न्यम	कॉम. बट्टला तिवया	153
12	मुम्मिदिवरम	कॉमरेड पेम्माटी स्वामी	107
13	उंडी	कॉम. वेतुकुटी शिवरामराजू	13260
			(तीसरा स्थान)
14	नेदाथोलु	कॉमरेड कस्तूरी सत्यप्रसाद	1691

लोकसभा चुनाव 2024 में एआईएफबी उम्मीदवारों को प्राप्त मत

नं.	राज्य	संसदीय क्षेत्र का नाम	उम्मीदवार का नाम	वोट सुरक्षित
1	आंध्र प्रदेश	1. नरसायवपेट	कॉमरेड टी. नागराजू	285
2		2. मछलीपट्टनम	कॉमरेड कोम्माराजू शिव नरसिम्हा राव	5254
3		3. कडप्पा	कॉमरेड अंकी रेड्डी सुरेश कुमार रेड्डी	755
4		4. नेल्लोर	कॉम. शैक शफी अहमद	1037
5		5. राजमपेट *	कॉम. पेनुमादु प्रतीप	5672
6		6. नांदयाला	कॉम. गोवर्धन	642
7	तेलंगाना	1. जाहिराबाद	कॉम. गुरांपु मचंदर	1769
8		2. महबुबाबाद	कॉमरेड अरुण कुमार मायापथी	39136 (चौथा स्थान)
9		3. वेवेल्ला	कॉम. कौंडा विश्वेश्वर रेड्डी	3748
10	महाराष्ट्र	1. माढा	कॉम. जागरूक सिद्धेश्वर भारत	3067
11		2. हातकणंगले	कॉम. दिनकरराव तुलसीदास चव्हाण	679
12		3. नागपुर	कॉमरेड संतोष तांजेवार	567
13		4. अमरावती	कॉम. भाऊराव वानकाडे	329
14		5. वर्धा	कॉम. रामाराव बाजीराव डोडास्कर	1438
15		6. मावल	कॉमरेड शिवाजीराव जाधव	1676
16		7. मुंबई उत्तर-पूर्व	कॉमरेड सुरेन्द्र सिबाग	678
17		8. धुले	कॉम. शिवाजी पाटिल	1001
18	मध्य प्रदेश	1. खजुराहो	कॉमरेड आर.बी.प्रजापति (आईएएस) सेवानिवृत्त)	50215 (तीसरा स्थान)
19	बिहार	2. पूर्णिया	कॉम. किशोर कुमार सादव	6854
20		2. पाटलिपुत्र	कॉम. माधुरी कुमारी	1302
21	जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू	कॉमरेड जहीर अब्बास भट्टी	984
22		2. अनंतनाग-राजीरी	कॉमरेड जावेद अहमद चौधरी	1562
23	ओडिशा	1. बेरहामपुर	कॉमरेड संतोष कुमार साहू	2291
24	पश्चिम बंगाल	2. कूच बिहार	कॉमरेड नीतीश चंद्र राय	30267 (तीसरा स्थान)
25		2. पुरुलिया	कॉमरेड धीरेन्द्र नाथ महतो	14572
26		3. बारासात	कॉमरेड संजीव चटर्जी	100000 (चौथा स्थान)
27	उत्तर प्रदेश	1. कानपुर	कॉम. प्रशस्त धीर	465
28		2. कन्नौज	कॉम. सुभाष चंद्र दोहरे	801
29		3. भदोही	कॉमरेड सुशील	5261
30		4. मिर्जापुर	कॉमरेड समीर सिंह पटेल	3487
31		5. बस्ती	कॉमरेड हाफिज अली	2988
32	दिल्ली	1. पश्चिमी दिल्ली	कॉमरेड चरणजीत सिंह	619
33		2. दक्षिण दिल्ली	कॉम. (डॉ.) गौतम आनंद	540

संविधान की रक्षा का जनादेश

पेज 1 से जारी...

देश में पिछले कई वर्षों से चल रहे किसान, मजदूर, युवा और छात्र महिला आंदोलनों ने इस चुनाव के नतीजों को काफी हद तक प्रभावित किया है। जिन क्षेत्रों में ये आंदोलन मजबूत रहे हैं, वहां भाजपा और उसके सहयोगियों ने काफी सीटें खो दी हैं। ऐसे संघर्षों को समन्वित और मजबूत करने के लिए वामपंथी दलों के जन संगठनों द्वारा निर्माई गई भूमिका अत्यधिक सराहनीय है। मजदूर वर्ग, जिसके प्रयासों से सकल घरेलू उत्पाद उत्पन्न होता है, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण, बढ़ती असमानता और सरकार की श्रम-विरोधी नीति के कारण यह वर्ग बहुत दुखी है। बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के विदेश प्रवास ने शहरी-ग्रामीण भेद के बावजूद युवा पीढ़ी के बीच सरकार विरोधी भावना को बढ़ा दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में युवा बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे अधिक 45.4 प्रतिशत है। सामान्य बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत है, जो उस देश में कई प्रकार के अल्प-रोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जहां लगभग 94 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। लोगों ने धार्मिक संप्रदायवाद के उद्देश्य से प्रधान मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के चुनाव अभियान को खारिज कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसे मोदी सरकार की मुख्य उपलब्धि के रूप में उजागर किया गया था और इसके उद्देश्य से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को लोगों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में भाजपा उम्मीदवार की शानदार हार से है, जिसमें अयोध्या भी शामिल है और वाराणसी में नरेंद्र मोदी के बहुमत में भारी कमी आई है। भारत का चुनाव आयोग, जिसे एक निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, ने परेशान करने वाला व्यवहार दिखाया है। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि चुनाव आयोग ने मोदी के नफरत भरे भाषण के लिए जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, खासकर राजस्थान के बांसवाड़ा में उनके कुख्यात भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने मुस्लिम नागरिकों को 'घुसपैटिए' कहा था। चुनाव आयोग ने नफरत भरे भाषण के इस और अन्य मामलों के बारे में कुछ नहीं किया, जिससे एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पर गंभीर संदेह पैदा हो गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का मानना है कि अगर भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी समूह इंडिया ब्लॉक ने शुरुआत में दिखाए गए उत्साह और एकता को बनाए रखा होता, तो चुनाव परिणाम अलग होते। इंडिया ब्लॉक के तत्वावधान में देश के प्रमुख शहरों में सामूहिक रैलियां करने के फैसले को स्थगित करने और प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों द्वारा छोटे दलों को मान्यता देने से इनकार करने से इंडियन फ्रंट की एकता पर गंभीर असर पड़ा। इंडिया ब्लॉक को आकार देने की पहल करने वाले नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण क्षण में दूसरी तरफ कूद पड़े और ममता बनर्जी की इस बारे में उतार-चढ़ाव भरी टिप्पणियां भी आई थीं कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक में रहेगी या नहीं और कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिए गए अनावश्यक बयानों ने भी यह धारणा बनाई कि इंडिया ब्लॉक में एकता का अभाव है। कई जगहों पर, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के नेता लोगों को यह भरोसा दिलाने में विफल रहे हैं कि विपक्षी मोर्चा भाजपा और संघ परिवार के उम्मीदवारों को हरा सकता है।

(19-20 जून 2024 को आयोजित एआईएफबी की सीसी में पारित प्रस्ताव)

अब हिंदुत्व का क्या होगा?

संगठित नफरत के कारण समाज में जो तीखा धुवीकरण हुआ है, उसे खत्म करना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 272 के बहुमत के आंकड़े को पार करने में विफल होने के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन फिर से महत्वपूर्ण है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और एनडीए सरकार का नेतृत्व किया, तो सरकार में भाजपा की राजनीति की मजबूत छाप थी। उस समय हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल अन्य चीजों में संविधान की समीक्षा के लिए वेंकटाचलैया आयोग की नियुक्ति, पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण और पाठ्यक्रम में ज्योतिष और पौरहित्य (अनुष्ठान) के पाठ्यक्रम शामिल करना शामिल था। 2014 और 2019 में दो बार मोदी एनडीए के रूप में सत्ता में आए, लेकिन चूंकि भाजपा के पास अपने दम पर भारी बहुमत था, इसलिए सरकार के अन्य घटक 'साइलेंट मोड' पर थे और भाजपा ने आक्रामक रूप से अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को लॉन्च किया, जिसमें राम मंदिर का निर्माण और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल था। इसके अलावा, जिन लोगों को 'फ्रिंज एलिमेंट्स' कहा जाता था, उन्होंने बीफ के बहाने मुसलमानों और दलितों की हत्या की और 'लव जिहाद' के हौवे को खुली छूट दी, जिससे राज्य से उन्हें कोई दंड नहीं मिला। संवैधानिक संस्थाओं की अधीनता इस मोदी सरकार की अन्य सत्तावादी प्रवृत्तियों ने प्रमुखता हासिल

की, साथ ही मुख्यधारा के मीडिया को 'गोदी' मीडिया में बदल दिया गया। इन सबने विपक्ष को जगाया और इंडिया ब्लॉक के रूप में एक साथ आने के लिए कहा। इस गठन के अस्तित्व में आने के बावजूद, मोदी और भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के इर्द-गिर्द केंद्रित किया। कांग्रेस के अधिकांश अन्य नारे और वादे हिंदू विरोधी और केवल मुसलमानों के लिए बने नारे बन गए। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैटिए और 'अधिक बच्चे पैदा करने वाला' समुदाय कहा। मोदी का प्रचार उस समय एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके लिए मुजरा (एक नृत्य जो मुगल शासन के दौरान उभरा) करेगी। व्यवस्था इस हद तक दुरुस्त कर दी गई है कि कई मुसलमानों के नाम मतदाता सूची में जगह नहीं पाते और चुनाव बूथों पर कई मुसलमानों को पुलिस द्वारा वापस भेज दिया जाता है। मुसलमानों को प्रभावी रूप से दूसरे दर्जे के नागरिक में बदल दिया गया है और राजनीतिक रूप से अदृश्य बना दिया गया है। यह सब इस असहाय समुदाय के खिलाफ प्रचलित नफरत को बढ़ाता है। चूंकि भाजपा एनडीए के लिए प्रचारित '400 पार' और भाजपा के लिए 370 से अधिक तक पहुंचने में विफल रही, पिछले 10 सालों में

अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हुआ, उसके मद्देनजर यह पाखंड की पराकाष्ठा थी। इसका जिक्र करना उचित नहीं है, आने वाले समय में अल्पसंख्यकों के लिए क्या होने वाला है? हाशिये पर पड़े तत्वों को मिलने वाली छूट में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि, यह एक बड़ी शर्त है, क्योंकि वे व्यवस्था में अच्छी तरह से जड़ जमा चुके हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी इस छिटपुट मुस्लिम विरोधी हिंसा के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। मोदी पार्टी की दबंगई के खिलाफ वे कितने कारगर साबित हो पाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। हिंदुत्व आंदोलन द्वारा फैलाई गई नफरत इतनी व्यापक है कि इसे रोकना आसान नहीं होगा।

संभावना है कि हिंदुत्व की राजनीति का तीसरा स्तंभ, समान नागरिक संहिता, स्थगित हो सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, एक लटकती तलवार की तरह है और समय ही बताएगा कि भाजपा इसे लागू करने के लिए कितना दबाव डालेगी। निश्चित रूप से शाहीनबाग उल्लेखनीय आंदोलन था। भाजपा इस पर तब तक जोर नहीं देगी जब तक उन्हें ऐसा न लगे कि वे नायडू और नीतीश के बावजूद अपना रास्ता बना सकते हैं, जो इन मामलों में अधिक चतुर

हैं। ध्यान दें कि नायडू अपने 'मुसलमानों के लिए आरक्षण' के मुद्दे से नहीं हटे हैं। जाति जनगणना का दूसरा प्रमुख मुद्दा, जिसका भाजपा विरोध करती है, पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश ने ही इसकी शुरुआत की थी। इसके लिए एक मजबूत राष्ट्रीय भावना है और मोदी के इस प्रचार के लिए बहुत कम समर्थन है कि इंडिया गठबंधन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को हटाकर मुसलमानों को दे देगा। मुसलमानों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा गठबंधन द्वारा इस समुदाय के खिलाफ फैलाई गई नफरत सामाजिक सोच में गहराई तक समा गई है। मुस्लिम विरोधी सोच समाज के एक बड़े हिस्से की धारणा का हिस्सा बन गई है। पाठ्यपुस्तकों में बदलाव, मीडिया की भूमिका और जुबानी प्रचार से आरएसएस और भाजपा का लगातार काम आसान हो गया है। ये मिथक और गलत धारणाएं ही वे ठोस स्तंभ हैं जिन पर नफरत का निर्माण किया जाता है और हिंसा और उसके बाद धुवीकरण लाया जाता है। हालांकि 2024 के चुनावों में आरएसएस की भूमिका के बारे में और विश्लेषण

की जरूरत है, लेकिन यह उनकी साजिशें हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत को जिंदा रखती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोदी शासन के दौरान आरएसएस की शाखाओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। ओडिशा जैसे राज्य में जहां कंधमाल में हिंसा हुई और पास्टर स्टेंस को जिंदा जला दिया गया, वहां अब भाजपा फिर से सत्ता में है। जबकि केरल में भाजपा ने विभिन्न कारणों से ईसाइयों के एक वर्ग को जीत लिया। इस संगठन द्वारा किए गए कार्यों के कारण समाज में जो गहरा धुवीकरण हुआ है, उसे दूर करना आसान नहीं है। आरएसएस जो कर रहा है, उसे हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने अच्छी तरह पहचाना था, जब उन्होंने 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिखा था, 'उनके सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे थे, जिसके परिणामस्वरूप देश को गांधीजी को अमूल्य जीवन का बलिदान देना पड़ा'। हमारे राजनीतिक जीवन के इस पहलू पर अंकुश नहीं लगाया गया और यह समाज के धार्मिक विभाजन को तेज करने के लिए हर अवसर का उपयोग करते हुए एक बहुत-सिर वाले हाइड्रा में विकसित हुआ। हम सामाजिक समझ को जकड़ने वाली भारी नफरत को खत्म किए बिना अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत नहीं बना सकते। (द्वारा राम पुनियानी-सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के अध्यक्ष हैं।)

40 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर, ईवीएम वोटों की गिनती ईवीएम...

पेज 8 से जारी...

ईवीएम वोट डाले गए लेकिन 1,031,784 ईवीएम वोट गिने गए, यानी 460 वोट नहीं गिने गए। भाजपा के मुकेश राजपूत ने 2,678 वोटों के अंतर से सीट जीती। जीत का अंतर घाटे से बड़ा है। इसलिए, कुछ लोग सोच सकते हैं कि पुनर्गणना की आवश्यकता नहीं है। यूपी के चुनाव आयोग ने कहा है कि जब अंतर घाटे से कम हो तो आप पुनर्गणना करा सकते हैं। लेकिन, चूंकि घाटा मार्जिन का 50% है (इनमें से तीन मामलों में), इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी

प्रक्रिया की कमियों को दर्शाता है। एक राय यह भी है कि इन सीटों और अन्य सीटों से हारने वाले उम्मीदवारों, जहां जीत का अंतर बहुत कम था, को 100% वोटों की गिनती की मांग करनी चाहिए। अगर ईवीएम में खराबी थी या पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई लिपिकीय त्रुटि की गई थी तो वीवीपेट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की संख्या में कमी के बारे में की गई टिप्पणियों के बावजूद, अन्य गंभीर प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है:

1. चुनाव आयोग अतिरिक्त मतों की गणना कैसे कर सकता

है, अर्थात्, डाले गए मतों से अधिक मतों की गणना की गई?

2. चुनाव आयोग सामान्य विवरण देने के बजाय संसदीय क्षेत्रवार कम या अधिक ईवीएम मतों की गणना पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है?

3. वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि डाले गए और गिने गए मतों के बीच का अंतर मॉक पोल डेटा को न हटाने के कारण है?

4. क्या चुनाव आयोग यह स्वीकार कर रहा है कि फॉर्म 17सी में उल्लिखित मतदान किए गए मतों की संख्या और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण इकाइयों में दर्ज मतों की संख्या में विसंगतियां थीं?

5. औसतन, एक ईवीएम प्रति मतदान बूथ 700 से 800 मत दर्ज करता है। फिर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कम मतों की संख्या 20-30 वोट जितनी कम क्यों है?

6. चुनाव आयोग ने ईवीएम में डाले गए सभी वोटों की गिनती क्यों नहीं की और अगर जरूरत पड़ी तो वीवीपीएटी की जांच उन जगहों पर क्यों की गई जहां जीत का अंतर बहुत कम था?

7. क्या चुनाव आयोग जनता को बताएगा कि कितनी ईवीएम अलग रखी गई और क्यों?

2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की ईमानदारी अपने सबसे निचले

स्तर पर पहुंच गई, खासकर तब जब उसने डाले गए वोटों की पूरी संख्या बताने में अनिच्छा दिखाई। मैंने ईमेल और एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के जरिए ईवीएम में डाले गए वोटों और गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या के बीच विसंगति के बारे में चुनाव आयोग से पूछा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। चुनाव आयोग के जवाब मिलने पर इस लेख को अपडेट किया जाएगा। (पूनम अग्रवाल एक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, अधिवक्ता और एक्सप्लेनएक्स यूट्यूब चैनल की संस्थापक हैं। -सौजन्य 'द वायर')

140 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ईवीएम वोटों की गिनती वोटों से ज्यादा क्यों?

कुछ मामलों में गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या ईवीएम वोटों की संख्या से 0 कम है। हालांकि, ऐसा क्यों हो सकता है, इसके लिए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन कुछ मामलों में 'घाटा' संबंधित सीटों पर जीत के अंतर का लगभग आधा है।

नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है।

2019 के लोकसभा चुनाव में, मैंने सबसे पहले 'द क्विंट' में ईवीएम वोटों और गिने गए ईवीएम वोटों के डेटा के बीच पाई गई विसंगतियों के बारे में रिपोर्ट की थी।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा 2019 में दायर याचिका के आधार पर इस मामले की सुनवाई पांच साल बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने 2019 के चुनावों के दौरान कई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पाई गई विसंगतियों के सभी दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं और मीडिया ने चुनाव आयोग के ऐप पर प्रकाशित मतदान किए गए वोटों की अनुमानित संख्या के आंकड़ों पर विचार किया था और इसीलिए उनका डेटा गिने गए वोटों की वास्तविक संख्या से मेल नहीं खाता। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विसंगतियां

दिखाते हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव आयोग के आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि दमन और दीव, लक्षद्वीप और केरल के अटिंगल जैसे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या एक स्थान पर अंतर दो वोटों के बीच था और दूसरे में 3,811 वोटों के बीच था। ऐसे मामले भी हैं, जिनमें दावा किया गया था कि डाले गए वोटों की तुलना में कम वोटों की गिनती की गई है। उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या ईवीएम वोटों की संख्या से कम थी, सबसे अधिक अंतर -16,791 वोट का था। यहां शीर्ष तीन निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां ईवीएम वोटों की संख्या में अधिकता हुई। चुनाव आयोग ने गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या और डाक वोटों की संख्या का अलग-अलग उल्लेख किया है।

(चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें) इसके अलावा, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के सदस्यों से बड़े विरोध के बाद 2024 के चुनाव में डाले गए ईवीएम वोटों की पूर्ण संख्या जारी की। चुनाव के पहले पांच चरणों के लिए, चुनाव आयोग ने केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों का प्रतिशत (कुल मतदाताओं की संख्या) जारी कर प्रस्तुत किया था। 25 मई को चुनाव आयोग ने पहले पांच चरणों में ईवीएम से डाले गए वोटों की संख्या का डेटा जारी करते हुए कहा कि "डाले गए वोटों

की संख्या में कोई बदलाव संभव नहीं है"। इसके प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि डेटा में डाक मतपत्रों की संख्या शामिल नहीं है। कुछ दिन पहले, जब एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर वोटों की संख्या में कमी को लेकर चर्चा शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि आयोग के डेटा में वोटों की संख्या

संसदीय क्षेत्र	मतों की गिनती	डाले गए वोट	अंतर
करीमगंज (असम)	1,140,349	1,136,538	3,811
मंडला (मध्य प्रदेश)	1,531,950	1,530,861	1,089
ओंगोल (आंध्र प्रदेश)	1,401,174	1,399,707	1,467
टिप्पणी: पूलम अलावाल डेटाबेस के साथ बनाया गया			
और यहां शीर्ष तीन सीटें हैं जहां ईवीएम वोटों की गिनती में कमी थी।			
संसदीय क्षेत्र	मतों की गिनती	डाले गए वोट	अंतर
तिरुवल्लूर (तमिलनाडु)	1,413,947	1,430,738	-16,791
कोकसगडार (असम)	1,229,546	1,240,306	-10,760
डेकनाल (ओडिशा)	1,184,033	1,193,460	-9,427
टिप्पणी: पूलम अलावाल डेटाबेस के साथ बनाया गया			

में कमी दिखाई दे सकती है, क्योंकि कुछ मामलों में, कुछ मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों की गिनती "आयोग द्वारा जारी किए गए मौजूदा प्रोटोकॉल और विभिन्न मैनुअल और हैंडबुक में दिए गए अनुसार" नहीं की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि "जिन मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों की गिनती नहीं की जाती है, वे दो श्रेणियों में आते हैं":

"(1) जहां पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले गलती से नियंत्रण इकाई से मॉक पोल डेटा को साफ करने में विफल रहता है या वह

वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले वीवीपीएटी से मॉक पोल परिचियों को हटाने में विफल रहता है।

(2) नियंत्रण इकाई में डाले गए कुल वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 17-सी में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं और जो गलती से गलत संख्या दर्ज करते हैं। उपरोक्त दो श्रेणियों के मतदान

अधिशेष वोट कैसे गिने गए। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम में जादुई तरीके से अधिक वोट कैसे दर्ज हो गए? ईवीएम वोटों की संख्या डाले गए ईवीएम वोटों की संख्या से कम क्यों हो सकती है, इसके लिए चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, लेकिन उससे पहले इन चार निर्वाचन क्षेत्रों पर विचार करें जहां जीत का अंतर बहुत कम था। सबसे पहले, महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पश्चिम में 951,580 ईवीएम वोट डाले गए थे, लेकिन 951,582 ईवीएम वोट गिने गए, यानी दो अधिशेष वोट गिने गए। शिवसेना के रवींद्र दत्ताराम वाईकर ने शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल गजानन को हराकर महज 48 वोटों के सबसे कम जीत के अंतर को हासिल किया। दूसरे, राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में 1,238,818 ईवीएम वोट डाले गए लेकिन 1,237,966 ईवीएम वोट गिने गए, यानी 852 वोट गिने नहीं गए तीसरा, छत्तीसगढ़ के कांकर में 1,261,103 ईवीएम वोट डाले गए लेकिन 1,260,153 ईवीएम वोट गिने गए, यानी 950 वोट नहीं गिने गए। भाजपा के भरोजराज नाग ने 1,884 वोटों के मामूली अंतर से सीट जीती।

चौथा, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1,032,244

शेष पेज 7 पर...

जन गर्जन हिन्दी मासिक ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय समिति के लिए देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद सदस्य द्वारा टी-2235/2, अशोक नगर, फैंज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 से मुद्रित तथा प्रकाशित। दूरभाष : 28754273
संपादक : देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद
मुद्रण स्थल : कुमार ऑफसेट प्रिंटेर्स, 381, पटपड़ गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092 वेबसाइट: www.forwardbloc.org
ईमेल: biswasd.aifb@yahoo.co.in
कम्प्यूटर कम्पोजिंग : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक, नेताजी भवन, नई दिल्ली

जन गर्जन

नेताजी भवन,
टी-2235/2, अशोक नगर, फैंज रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दूरभाष : 011-28754273

जन गर्जन

ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का हिन्दी मासिक

सेवा में,

